

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2020/00077(77/2020)

1. फूलाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीचन्द पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. विनोद पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

—अपीलांटस

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र रिछपाल जाति जाट साकिन ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंटस



अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

दिनांक 12.03.2020 प्रकरण संख्या 84/2018

अनवान मोहर सिंह बनाम फूलाराम आदि

उपस्थिति:-

- श्री हवासिंह पुनिया, अभिभाषक अपीलार्थी/गण
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक 11.5.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत एक दावा पेश किया एवं दावा के साथ एक प्रार्थना-पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया, जिसमें कथन किया कि रोही मोजा ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर कुल 14.3650 हैक्टेयर भूमि में सायल 1/2 हिस्सा गैर सायल नं. 1 का 1/4 हिस्सा गैर सायल नं. 2 ता 4 ब.हि.ब 1/4 हिस्सा के खातेदार दर्ज है सायल एवं गैर सायलान अपने हक व हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे हैं लेकिन भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है जिससे लगान काश्त एवं सीव का झगड़ा रहता है इसलिए खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। अब गैर सायलान सायल की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं इसलिए गैरसायल के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध मांगा। गैरसायल ने प्रार्थना-पत्र का विरोध किया एवं कथन किया कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दोनों पक्षों के कथनोंसे साबित है कि भूमि का बंटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार काबिज हैं एवे प्रस्तुत दस्तावेजों से भली भांति साबित होता है कि गैरसायल अपीलाट ने 2 ता 4 ने अपने बंटवारा में प्राप्त भूमि में सभी की सहमति से पानी की डिग्गी व कोठा का निर्माण किया हुआ है, इस बात पर कोई गौर नहीं किया गया। विवादित भूमि मुश्तरका खाते की हैरेस्पोजेण्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानूनी स्थिति के मुताबिक एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोजेण्ट्स ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। किशनाराम पुत्र रिछपाल ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह तर्ककर दिया है इसलिए विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील



ban
राजस्थान अपील प्राधिकारी
जयपुर

नहीं होते हैं ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है। प्रथम दृष्टाया मामला, सुविधा का सन्तुलन आर्थित क्षति अपीलान्ट के पक्ष में साबित हो हैं फिर भी उन पर कोई गौर नहीं किया गया है। मातहत अदालत ने सजिसाना तरीके से सिर्फ अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट सं० 1 ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि में उसका प्रार्थना-पत्र में वर्णितानुसार हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तर्का है और सायल व गैरसालान ने प्रश्नगत 14.3650 है० भूमि का खाता व लगान मुश्तरका है उक्त खाते में काफी हिस्सेदार सह भागीदार होने के कारण भूमि काश्त की सीमाएं तथा अधिकारों के बाबत फरीकेन दावा में आपस में तनाजात रहते हैं और खेत में बनी डिग्गी कोठा को लेकर झगड़ा रहता है इसलिए सायल अपना उक्त भूम का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त तक्सीम करवाकर अलग कायम करवाने के अधिकारी है सायल ने अपनी भूमि में काफी परिश्रम व सुधार कर उपजाउ बना रखा है और अपने खेत में पानी डिग्गी और कृषि उपकरण व सुविधा होतु कोठा बना रखा है। तथा मुश्तरका खाता के आधार पर गैरसायल उनके कब्जा कात की व सुधारी हुई भूमि पर काबिज होना चाहते हैं जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है, अपूर्णाय क्षति होती है। इसलिए विचारण न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है विधि सम्मत है अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्नगत भूमि मुश्तरका खाते की भूमि है , जिसमें सायल का 1/2 हिस्सा गैर सायल नं. 1 का 1/4 हिस्सा, गैर सायल नं. 2 ता 4 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोजेण्ट दोनों रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार हैं। बहस में आये तथ्यों के अनुसार पक्षकारों के



Law
राजकीय अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मध्य बाहमी बंटवारा कर लिया है। जब बाहमी बंटवारा हो चुका है तो एक दूसरी की भूमि में दखल दिया जाना उचित नहीं है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें किस पक्षकार का कितना हक हिस्सा है यह मूल वाद में तय होना है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुलता न हो, उभयपक्ष के हक अधिकार सुरक्षित रहें, भूमि सुरक्षित रहे ऐसी स्थिति में स्थगन जारी किया उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना समुचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

9.

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.03.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



11/5/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़